आज़ादी का अमृत महोत्सव

# साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 09.10.2023 से 15.10.2023)

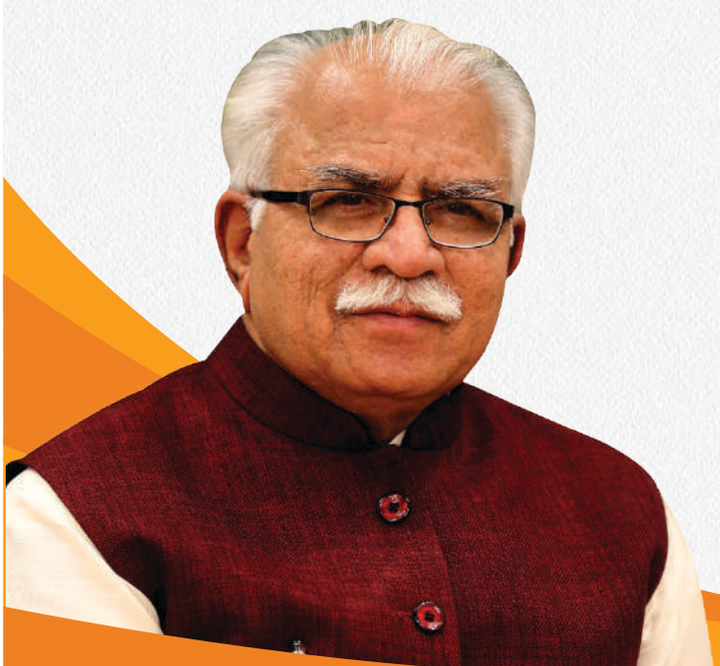

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

# साप्ताहिक सूचना पत्र

## एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक

(दिनांक 09.10.2023)

**प्रभाव :** मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यहां हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) और विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) की बैठक में 1645 करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रेक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई।

बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 29 करोड़ रुपये की बचत की गई है। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में सिंचाई, क्रिड, पुलिस, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएन एल), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शुगरफेड, विकास एवं पंचायत विभागों के 29 एजेंडे, डीएचपीपीसी में 7 एजेंडे तथा हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी में सिंचाई, लोक निर्माण (भवन और सड़कें) सहित कुल 20 एजेंडे रखे गए और सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा ओल्ड पुलिस लाईन, हिसार में 48 टाईप–II तथा 24 टाईप–III तीन मंजिला मकान बनाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गांवों

# साप्ताहिक सूचना पत्र

में स्ट्रीट लाइट लगाने, 63 केवीए ट्रांसफार्मर की खरीद, शुगरफेड के लिए पीपी बैग, भारतनेट परियोजना के तहत गांवों में फायबर इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए भी कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही, 2 हजार लीटर क्षमता की 36 सीवेज सफाई मशीनों की खरीद को मंजूरी दी गई। इससे छोटी गलियों में जाकर सीवरेज की सफाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

बैठक में मंजूर किए गए कॉन्ट्रेक्ट में मुख्यतः हिसार–बालसमंद सड़क को 4 लेन बनाने, उचाना से लितानी सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य, जिला रेवाड़ी में सैनिक स्कूल, गोठरा, टप्पाखोड़ी में आवासीय भवनों का निर्माण, जिला गुरुग्राम के जमालपुर गांव में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व जलापूर्ति में सुधार तथा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, साहा अंबाला के सेक्टर–1, 2 व 3 में सड़कों का सुदृढ़ीकरण का कार्य शामिल है।

# साप्ताहिक सूचना पत्र

## हिसार जनसंवाद कार्यक्रम

(दिनांक 10.10.2023)

**प्रभाव :** माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के आईजी सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर कहा है कि प्रदेश में नागरिकों के घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइन को हटाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 151 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया हैं। घरों के ऊपर से गुजरने वाली लाइन की समस्या का समाधान करने के लिए बिजली विभाग को निर्देश जा चुके है। उन्होंने बिजली विभाग से कहा कि भविष्य में बिजली की लाइन के नीचे निर्माण नहीं होने दिया जाये। उतराखंड में हुए हादसे में जान गंवाने वाले नागरिकों को दो मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी। इससे पूर्व उन्होंने रेडक्रॉस की सहायता से दिव्यांगों को दिव्यांग जनसहायक उपकरण भी प्रदान किये। उन्होंने घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाये गये उत्पादों की स्टाल का अवलोकन किया। हरियाणा देश का बुजुर्गों को सर्वाधिक पेंशन देने

# साप्ताहिक सूचना पत्र

वाला राज्य है। बुजुर्गों की पेंशन में जल्द ही बढ़ौतरी करके तीन हज़ार रुपये किए जाएँगे। अब प्रदेश के नागरिक को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ते। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वतः ही पेंशन बन रही है। जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने मौक़े पर ही 22 लोगों की पेंशन बनवाकर कार्ड प्रदान किए।

जनसंवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष दिव्यांग नागरिकों ने जिला में कुछ राशन डिपुओं पर गड़बड़ की शिकायत की। उन्होंने राशन डिपुओं पर फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन लेने सहित राशन से जुड़ी अन्य शिकायतों की जाँच एंटी करप्शन ब्यूरो को करने के आदेश दिये। उन्होंने 37 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली हिसार से खानक और 8 करोड़ की लागत से बनने वाली हिसार से बालसमंद रोड़ के निर्माण की घोषणा की। 26 करोड़ रुपये की लागत की 14 सड़कों के टेंडर पहले ही हो चुके है, जिनपर जल्दी काम शुरू हो जाएगा।

लोगों के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना लाभप्रद सिद्ध हो रही है। लोगों को पाँच लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज इस योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है। हिसार विधानसभा क्षेत्र में 77566 आयुष्मान कार्ड बनवाए है। जिनमें से 868 कार्डधारकों ने 2 करोड़ 74 लाख राशि का इलाज करवाकर योजना का लाभ उठाया है। दयालु योजना के तहत 75 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई गई है।

# साप्ताहिक सूचना पत्र

## प्रगतिशील किसान मेला

(दिनांक 10.10.2023)

**प्रभाव :** हिसार कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि विकास मेले में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हरियाणा किसान प्रधान प्रदेश है। यहाँ के किसानों ने कृषि के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों में अपना परचम देश और दुनिया में लहराया है। उन्होंने कहा कि हर साल किसानों को नवाचार और तकनीक बारे ज्ञानवर्धन के लिए कृषि मेला आयोजित किया जाता है। किसानों का उत्साह इस मेले के प्रति बढ़ा है। किसानों ने नई फसलों के साथ साथ नकदी फसलों की खेती करनी शुरू कर दी है। सरकार भी किसानों को खेती और तकनीक बारे जानकारी देने के साथ उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं। किसानों की बदौलत हरियाणा आज तरक्की के मामले में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। खेती हमारी जान है तो पहलवान हमारी शान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज आधुनिकता का युग है। खेती

# साप्ताहिक सूचना पत्र

में नई तकनीक और मशीनीकरण का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। आधुनिकता ने किसानों के काम को और सुलभ कर दिया है।

उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों ख़ासकर कृषि विश्वविद्यालय हिसार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वैज्ञानिकों ने नए नए बीजों की किस्मोंकी खोज की है, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने किसानों से अपने खेत की मिट्टी और पानी की जाँच करवाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे किसानों को अपने खेत में होने वाली फसल और कौन सी खाद उपयोग में लाई जानी सही है, इसकी जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीद रही है।

कुछ फसलों को भावांतर भरपाई के ज़रिए ख़रीदा जा रहा है। अभी बाजरा की फसल को हेफ़ेड द्वारा 2200 रुपये प्रति क्विंटल पर ख़रीदा जा रहा है। सरकार किसानों को इस पर 300 रुपये प्रति क्विंटल भावान्तर भरपाई योजना

# साप्ताहिक सूचना पत्र

का लाभ दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि एसवाईएल नहर पर हमारे हक़ पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहर का निर्माण अवश्य होगा। उन्होंने कहा कि एसवाईएल हरियाणा का हक़ है और इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र लागू करवाया जाएगा। हरियाणा कृषि विकास मेले के समापन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संकलित तीन पुस्तकों का विमोचन किया। यह सभी पुस्तक कृषि तथा किसान उत्थान को लेकर लिखी गई है। इन पुस्तकों में कृषि बागवानी प्राकृतिक खेती फसल उत्पादन बिक्री समेत नवीनतम कृषि तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी जुटाई गई है ताकि किसान घर बैठे हर प्रकार की जानकारी हासिल कर सके।

# साप्ताहिक सूचना पत्र

## आरबीआई द्वारा अनुमोदित तीन टीआरईडीएस संस्थाओं के साथ MOU का एक्सचेंज

**(दिनांक 10.10.2023)**

**प्रभाव :** माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आज प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उद्योग और वाणिज्य विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुमोदित तीन टीआरईडीएस (व्यापार प्राप्य ई डिस्काउंटिंग सिस्टम) संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) का आदान–प्रदान किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा मुख्य रूप से कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन घटती भूमि जोत के कारण इस क्षेत्र का दायरा सीमित है। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर आपूर्तिकर्ताओं, खरीदारों, बैंकरों और एनबीएफसी की सक्रिय भागीदारी, एमएसएमई के बीच डिजिटल ऋण

और उठाव को बढ़ावा देने के माध्यम से एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की वर्तमान आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार धीरे–धीरे अपने विभागों और पीएसयू को टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर ला रही है, जिससे एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को समय पर और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित हो सके।

टीआरईडीएस एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने कार्यक्रम के लिए भी एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है और इसे एमएसएमई के लिए भुगतान चौनल बनाने के लिए सरकार और बैंकरों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। आरबीआई के अनुसार, 'रिकोर्स' आधार पर फैक्टरिंग लेनदेन बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे। टीआरईडीएस संस्थाओं ने लेनदेन को सुरक्षित, संरक्षित और गोपनीय रखते हुए प्रतिभागियों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक और लेनदेन डेटा से समझौता न किया जाए, बुनियादी ढांचे और एप्लिकेशन स्तर पर प्रभावी सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। यह एमओए नकदी संकट से जूझ रहे एमएसएमई के बीच तरलता बढ़ाने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।

यह कदम एमएसएमई विक्रेताओं को कम लागत तथा कोई कोलेटरल फंडिंग नही प्रदान करके हरियाणा में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा, जो पहले विलंबित भुगतान और तीव्र कार्यशील पूंजी की कमी का खामियाजा भुगत रहे थे।

# साप्ताहिक सूचना पत्र

## हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक की अध्यक्षता

(दिनांक 11.10.2023)

**प्रभाव :** माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक की अध्यक्षता कर कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उद्योग जगत हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति–2020 के तहत हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करवाए। इसके अलावा, उद्योग नीति के तहत राज्य जीएसटी संग्रहण में भी बढ़ोतरी हो। बैठक में 1041 करोड़ रुपये के निवेश की चार परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। आईएमटी रोहतक में जेवी एसोसिएट को 100 एकड़ अतिरिक्त भूमि में आर एण्ड डी के विस्तार की भी मंजूरी दी गई। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति–2020 के तहत निर्धारित पूंजी निवेश पर निवेशक कम्पनियों को 119.54 करोड़ रुपये के विशेष सब्सिडी पैकेज को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें बिजली, राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी में छूट इत्यादि शामिल है।

# साप्ताहिक सूचना पत्र

## मंत्रिमंडल की बैठक

(दिनांक 11.10.2023)

**प्रभाव :** मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न एजेंडे पारित किये जोकि मुख्यतः निम्नप्रकार से हैं

**विभागों, बोर्डों, निगमों, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्य में भूमि की बाजार दर निर्धारित करने की नीति में संशोधन।**

**दीन दयाल जन आवास योजना (डीडीजेएवाई) में किफायती प्लॉटेड हाउसिंग नीति 2016 के खंड 2 (1) में संशोधन को मंजूरी प्रदान।**

**मीडियाकर्मियों की पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी।**

**राज्य में स्टेट कैरिज बसों के किराये में 5 रुपये तक के किराये को राउण्ड ऑफ करने की मंजूरी।**

**आवासीय भूखंडों को वाणिज्यिक उपयोग में बदलने की अनुमति देने और नियमित करने के लिए नई नीति की घोषणा।**

**अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने और नगरपालिका सीमा के भीतर नगर पालिकाओं या नगर सुधार ट्रस्टों द्वारा आवंटित एकल स्तरीय बूथ, दुकानों और सर्विस बूथों पर पहली मंजिल या बेसमेंट या दोनों के निर्माण के लिए नई अनुमति देने के उद्देश्य से एक व्यापक नीति को स्वीकृति प्रदान।**

**हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति, 2023 को मंजूरी।**

**पराली एक्स–सीटू प्रबंधन नीति, हरियाणा–2023 को मंजूरी प्रदान।**

माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट बैठक के उपरांत पत्रकार वार्ता के दौरान एक क्लिक से बाढ़ प्रभावितों के खाते में मुआवजा की 5 करोड़ 90 लाख 99 हज़ार की राशि ट्रांसफर की। पशुधन की हानि, घर की क्षति, वाणिज्यिक संपत्ति की हानि (ग्रामीण) और कपड़ों

# साप्ताहिक सूचना पत्र

,बर्तनों/घरेलू सामानों की हानि की भरपाई की लगभग पूरी राशि जारी की गई। इसी प्रकार 40 मृतकों के परिजनों को कुल 1 करोड़ 60 लाख रूपये का मुआवजा दिया गया है, शेष 7 मृतकों के सत्यापन का कार्य जारी है। अर्थात अब तक राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावितों को 7 करोड़ 50 लाख 99000 रूपये की राशि जारी की गई है। फसल के नुकसान की भरपाई का भी जल्द ही निर्धारित मानदंडों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का सत्यापन–कार्य पूरा कर लिया गया है और मुआवजे की गणना सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है।

प्रदेश सरकार को राज्य में 1,41,079 किसानों से करीब 6,87,077 एकड़ क्षेत्र में हुए फ़सल के नुकसान का दावा करने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा घरों की क्षति के लिए मुआवजे का दावा करने वाले 7,504 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमे ग्रामीण क्षेत्र से 6,057 और शहरी क्षेत्र से 1,447 आवेदन मिले हैं। प्रभावित लोगों द्वारा किये गए दावों को मंजूरी दे दी गई है और क्षतिपूर्ति पोर्टल पर मूल्यांकन और सत्यापन के अनुसार हाल ही में आई बाढ़ के कारण पशुधन की हानि, घर की क्षति, वाणिज्यिक संपत्ति की हानि (ग्रामीण) और कपड़ों ,बर्तनों/घरेलू सामानों की हानि के कुल 8456 दावे मिले जिनमे से 8449 का सत्यापन हो चूका है। इन सत्यापित दावों की भरपाई के लिए 5 करोड़ 90 लाख 99 हज़ार रूपये की राशि जारी कर दी है।

पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजे के वितरण के मानदंड 1,20,000 रुपये प्रति घर और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 10,000 रुपये प्रति पक्का मकान एवं 5,000 रुपये प्रति कच्चा मकान दिया जाएगा। अगर अब भी मुआवजे के भुगतान में कटौती से किसी को ऐतराज है, तो वे अपनी शिकायत उसी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जांच सही पाए जाने पर शिकायत का निवारण किया जाएगा।

# साप्ताहिक सूचना पत्र

## नगर निगमों के मेयरों व सीनियर डिप्टी मेयरों की बैठक

(दिनांक 12.10.2023)

**प्रभाव :** माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां हरियाणा निवास में राज्य के नगर निगमों के मेयरों व सीनियर डिप्टी मेयरों की बैठक की अध्यक्षता कर कहा कि मेयर एक बड़े क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में सत्ता का केन्द्रीकरण होता था, जबकि हमने सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया है। उन्होंने कहा कि कल की कैबिनेट बैठक में शहरों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। शहरों की छोटी सरकार के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने की कड़ी में नगर निगमों के मेयर को जे.ई. सहित ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को सस्पेंड करने के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा, उन्होंने बैठक में मेयरों की प्रशासनिक स्वीकृति को 2.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की

# साप्ताहिक सूचना पत्र

घोषणा भी की।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे लोगों को इस बारे में जागरूक करें ताकि मॉडल टाऊन जैसी पुरानी कॉलोनियों में चल रही शॉपिंग मॉल जैसी गतिविधियों को कानूनी रूप में नियमित करवा जा सके। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग की तरफ से नगर निगमों को तिसरी तिमाही का लगभग 600–700 करोड़ रुपया आवंटित किया जाना है।

मेयर अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का अनुमान तैयार करें और शीघ्र ही इसे सरकार को भिजवाएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में सरकार द्वारा 404 कॉलोनियां नियमित की गई हैं, जिनमें से 151 कॉलोनियां नगर निगमों के अंतर्गत आती हैं।

उन्होंने कहा कि नगर निगमों का दायरा बढ़ने से कई गांव इसमें शामिल हुए हैं तथा इन गांवों में लाल डोरे के दायरे से बाहर कई कॉलोनियां बन गई हैं, जिसमें कृषि भूमि भी शामिल है और इस पर नगर निगमों द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपये का सम्पति कर लगाया है, जिसे लौटाना होगा क्योंकि कृषि भूमि पर किसी प्रकार का सम्पति कर नहीं लगाया जा सकता।

सरकार द्वारा इन कॉलोनियों का सर्वे करवाया जाएगा ताकि वहां की सम्पतियों का भी क्रय व विक्रय हो सके।

# साप्ताहिक सूचना पत्र

## प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर अग्रोहा की पुरातात्विक विरासत को विकसित करने की मंजूरी

(दिनांक 14.10.2023)

**प्रभाव :** राखीगढ़ी की तर्ज पर जल्द ही सरकार अब ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा को विकसित करने जा रही है। अग्रोहा के पुरातात्विक स्थल को महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। इस स्थल के विकसित होने से ना केवल आस्था का यह केंद्र विश्व में अपनी पहचान बनाएगा बल्कि यह स्थल पर्यटन के रूप में भी विख्यात होगा। केंद्र सरकार ने अग्रोहा पुरातात्विक स्थल एवं निकटवर्ती क्षेत्र का समग्र विकास राखीगढ़ी मॉडल के अनुसार एमओयू के माध्यम से करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अन्वेषण एवं उत्खनन अनुभाग के निदेशक (अन्वेषण एवं उत्खनन) श्री परवीन कुमार मिश्रा ने पत्र लिखकर जानकारी दी है। उन्होंने हरियाणा सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के विशेष सचिव एवं निदेशक को लिखे पत्र में बताया कि अग्रोहा पुरातत्व स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की उत्खनन शाखा–द्वितीय और हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। खुदाई शुरू करने से पहले, संभावित क्षेत्रों में जीपीआर सर्वेक्षण जैसे अन्य सर्वेक्षण किए जाएंगे। हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग जीपीआर सर्वेक्षण के लिए वित्तपोषण करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार पुरातत्व स्थलों को विकसित करने का काम कर रही है। सरकार राखीगढ़ी की पुरानी सभ्यता को सुरक्षित रखना व उस स्थल को विकसित करने इत्यादि विषयों को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं प्रदेश सरकार ऐतिहासिक धरोहर लोहगढ़ को भी नया स्वरूप देने जा रही है। इसके साथ ही संत–महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को भी सरकार द्वारा जन–जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

# साप्ताहिक सूचना पत्र

## राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से विशेष चर्चा

(दिनांक 14.10.2023)

**प्रभाव :** माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान चंडीगढ़ से ऑनलाइन माध्यम से राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से चर्चा कर बताया कि राज्य के राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों के 7400 क्लासरूम में से 4035 स्मार्ट क्लासरूम बन चुके हैं, बकाया क्लासरूम्स को इस वर्ष स्मार्ट क्लासरूम में बदला जाएगा।

हर विद्यार्थी की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए इन विद्यालयों में शिक्षण के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इन विद्यालयों की दीवारों को ऐसे सजाया गया है, जिससे दीवारों पर शिक्षण सामग्री पेन्ट करवाकर शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है। इससे विद्यार्थी देखकर, पढ़कर तथा पेन्सिल के माध्यम से सीख सकते हैं। पूरे भवन को ही सहायक सामग्री में बदल दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत हम प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार कर रहे हैं, जिनमें नन्हे बच्चे की केजी कक्षा से युवा विद्यार्थी की पीजी कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से आह्वान किया कि बच्चा जिस क्षेत्र में निपुण है, उसी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।

आगे चलकर बच्चा क्या बने, इसका निर्णय उसे स्वयं लेने दे। उसका कैरियर बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। बच्चों की पसंद व अभिरुचियों को निखारने में मदद करें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए थ्री–एस यानी कि स्टडी, स्पोर्ट्स व स्कीन के समय में संतुलन बनायें। इसके साथ ही वह खेल के लिए भी समय निकाले ,मोबाइल फोन व इंटरनेट के आने से बच्चे पर जरूरत से ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, उनकी इस आदत पर अंकुश लगाएं।

# साप्ताहिक सूचना पत्र

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही उच्चकोटि की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय खोलने की प्रक्रिया 2017 में शुरू की थी। उस समय राज्य के 119 खण्डों में से हर एक खण्ड में एक राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय (बैग फ्री स्कूल) खोला गया था। शिक्षा प्रदान करने की दिशा में इन विद्यालयों की सफलता को देखते हुए स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों, पंचायतों. शिक्षाविदों व जनप्रतिनिधियों द्वारा और मॉडल संस्कृति विद्यालय खोलने की मांग उठने लगी। हमने उनकी मांग पर इन विद्यालयों का विस्तार किया और आज इनकी संख्या बढ़कर 1,419 हो गई है। इन विद्यालयों में 3 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये तक है, उनके लिए मॉडल संस्कृति

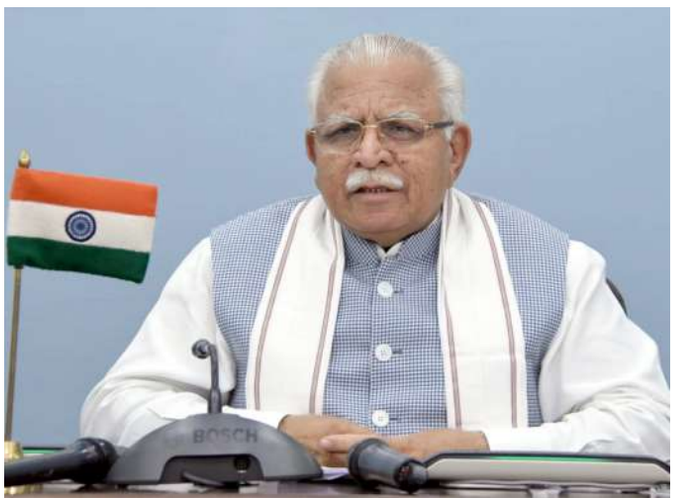


स्कूलों में शिक्षा निःशुल्क है। इन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे 65 प्रतिशत विद्यार्थी गरीब परिवारों के हैं। हमने ऐसे परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षा दिलवाने के लिए चिराग–योजना चलाई है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों का दाखिला कक्षा 2 से 12वीं तक करवाया जाता है। इन बच्चों की फीस सरकार भरती है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे प्रण लें कि वे अपने बच्चों को भरपूर प्यार, देखभाल और वर्तमान समय की जरूरत के अनुसार शिक्षा दिलवाएंगे। इसके लिए सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।

# साप्ताहिक सूचना पत्र

## सोशल मीडिया प्रतिनिधियों से मुलाकात

(दिनांक 14.10.2023)

**प्रभाव :** माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके सरकारी आवास संत कबीर कुटिर में सोशल मीडिया से संबंधित कई प्रतिनिधि मिले और राज्य में हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति,2023 के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। यह विज्ञापन नीति विशेष रूप से श्सोशल मीडिया न्यूज़ चौनलों के लिए तैयार की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज में सोशल मीडिया द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका को रेखांकित किया। प्रदेश सरकार मीडिया पेशेवरों के भविष्य को मजबूत करने और उन्हें आधुनिक युग में सच्चाई लिखने के लिए सशक्त बनाने हेतु यह नवीन कल्याणकारी नीति लेकर आई है। हाल ही में जो हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति, 2023 नीति बनाई गई है ,वह आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है और उन्हें पत्रकारों का दर्जा प्रदान करती है। यह मीडिया परिदृश्य में उनकी पहचान और प्रभाव में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सही साबित होगी। इस नीति में सोशल मीडिया पर चौनल के सबस्क्राइबर , फॉलोवर और पोस्ट वॉल्यूम जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया है।

# साप्ताहिक सूचना पत्र

## बरवाला में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम

(दिनांक 15.10.2023)

**प्रभाव :** माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामुदायिक केंद्र बरवाला में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुये निवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए गांव में जल्द ही सीवरेज की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इससे गांव में जलभराव की समस्या का निदान होगा और पानी की समुचित निकासी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा उन्होंने सामुदायिक केंद्र बरवाला का नाम शहीद राजपाल राणा के नाम से करने की भी घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि 26 अक्तूबर को वर्तमान राज्य सरकार के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे है और इस दौरान तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर पर भरपूर विकास कार्य हुए है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में सड़को के निर्माण के लिए 25–25 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है और सड़को का निर्माण

# साप्ताहिक सूचना पत्र

कार्य भी आरंभ हो चुका है। इसके अलावा इस बार हुई भारी बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुए पुल और सड़को के सर्वे का कार्य भी पूरा हो चुका है और इनकी मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले बुजर्गों को वृद्धा सम्मान पेशन के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे परंतु अब लाभार्थी को किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं बल्कि 60 वर्ष पूरा होते ही उसकी पेंशन स्वतः ही बन जाती है। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित ऐसे लोग जो 60 वर्ष के हो चुके है और जिनकी पेंशन नहीं बनी है वह मौके पर ही संबंधित विभाग द्वारा लगाए स्टॉल पर जाकर अपनी पेंशन बनवा सकते है। इसके उपरांत कार्यक्रम में उपस्थित संबंधित अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों की पेंशन बनाई गई । उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पैसा ना खर्च करना पड़े इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी व निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये वार्षिक तक की निशुल्क इलाज सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। बरवाला में 3 हजार

# साप्ताहिक सूचना पत्र

लोगों के आयुष्मान कार्ड बने है और 74 लोग इस सुविधा का लाभ उठा चुके है, जिनके इलाज पर 16 लाख रुपये खर्च हुए है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए चिरायु विस्तार योजना लागू की गई हैं, जिसके तहत 1 लाख 80 हजार से लेकर 3 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार मात्र 1500 रुपये जमा करवाकर 5 लाख रुपये तक का बीमा करवा सकते है।

इस योजना से 8 लाख अतिरिक्त परिवारों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में नौकरियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और खर्ची और पर्ची के आधार पर नौकरियां दी जाती थी परंतु वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में पंचकूला जिला में 606 युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी मिली है, जिसमें से 62 लोग बरवाला के है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारी बरसात के कारण जिला के जिन लोगों की संपत्ति को नुकसान हुआ है और जिन्होंने पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा अपलोड किया है, उसके लिए राज्य सरकार द्वारा 4.50 करोड रुपये की मुआवजा राशि जारी कर दी गई हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पोर्टल पर नुकसान का ब्योरा अपलोड नहीं किया था वह उपायुक्त को लिखित में आवेदन दे सकते है। अवैध खनन की समस्या पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तय सीमा से अधिक गहराई तक खनन किसी भी हालत में बदार्शत नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा प्रतिमाह खनन स्थलों की ड्रोन मैपिंग करवाई जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग को ओवरलोडिंग टिपरो पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओवर लोडिंग वाहनों की वजह से जहां सड़के टूटती है वहीं दुर्घटना के मामले बढ़ते है और पर्यावरण को भी नुकसान पंहुचता है।

# साप्ताहिक सूचना पत्र

## अंबाला के शहजादपुर में जन संवाद कार्यक्रम

(दिनांक 15.10.2023)

**प्रभाव :** माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहजादपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनता से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और सम्बंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित गति से समाधान करने के निर्देश दिये। उन्होंने शहजादपुर के सरपंच रविन्द्र सिंह की मांग पर शहजादपुर में सीवरेज व्यवस्था को मंजूर किया तथा उन्होंने जिला युवा शक्ति संगठन द्वारा संचालित राधा–कृष्ण बाल आश्रम नारायणगढ़ को संस्था की मांग पर पांच लाख रुपये की राशि आश्रम के निर्माण कार्यों के लिए देने की घोषणा की। उन्होने लोगों से संवाद करते हुए कहा कि उनके जन संवाद करने का मकसद भी यही है कि लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को जानना और सरकार द्वारा जो कार्य एवं जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा

# साप्ताहिक सूचना पत्र

रही है उनकी जानकारी देना। उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह के दौरान उनके जन संवाद कार्यक्रमों के दौरान लगभग 26 हजार एप्लीकेशन आई है जिनमें से 7 हजार का निवारण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं एवं शिकायतों को पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। उन्होंने कहा कि आने वाली 26 अक्टूबर को उनकी सरकार के 9 साल पूरे हो जायेंगे। इन 9 सालों में पिछली सरकारों की तुलना में वर्तमान सरकार ने दोगुने काम करवाए है और पैसा भी आधा खर्च किया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए किये गये प्रकल्पों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने पहली बार हर परिवार का परिवार पहचान पत्र बनवाया है। पीपीपी में दर्ज जानकारी पूरी तरह से सटीक है। पीपीपी के आधार पर किसी भी शहर की आबादी की सही जानकारी का पता चल जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जन संवाद कार्यक्रम मंद बनी लगभग एक दर्जन से अधिक वृद्धावस्था पेंशन के प्रमाण पत्र बुजुर्गों को सौंपकर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होने कहा कि

# साप्ताहिक सूचना पत्र

पिछले एक साल में 90 हजार लोगों की पेंशन पीपीपी के माध्यम से लगी है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाना सबसे जरूरी है और पीपीपी के माध्यम से ही सरकारी योजनाओं व स्कीमों का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिलेगा। उन्होंने लोगों से सीधा संवाद करते हुए उनकी बात को सुना और अपनी बात को रखा।

किसान संगठनों व किसानों द्वारा नारायणगढ़ शुगर मिल का मामला रखते हुए गन्ने के बकाया भुगतान की समस्या रखी जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शुगर मिल का सिस्टम ठीक किया जा रहा है। इस शुगर मिल को 100 करोड़ रुपये हरको बैंक का देना है तथा 150 करोड के लगभग इरेड़ा का देना है, पिछले वर्ष 66 करोड़ का बकाया किसानों का था। शुगर मिल के मालिक पर केस दर्ज होने और उसके जेल में चले जाने के कारण शुगर मिल का सिस्टम बेहद खराब हो गया था जिसे धीरे–धीरे करके सरकार ने ठीक किया है और किसान हित में सरकार इस शुगर मिल को चला रही है और अगर यह शुगर मिल बंद हो गई तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का होगा। बिजली की लाइन शिफ्ट करने की समस्या पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में बिजली की लाइन के शिफ्ट करने के लिए 151 करोड रुपये की राशि मंजूर की गई है।

# साप्ताहिक सूचना पत्र

## अंबाला एयरपोर्ट का शिलान्यास

(दिनांक 15.10.2023)

**प्रभाव :** माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवरात्रों पर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए अंबाला के पहले घरेलू एयरपोर्ट का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। नवरात्रों के पहले दिन मां अंबा के नाम से बसे अंबाला के निवासियों को मनोहर सौगात मिली। उन्होंने कहा कि अंबाला में हवाई अड्डा बनने से इस क्षेत्र में निवेश और उद्योग बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि 20 एकड़ जमीन पर टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसपर लगभग साढ़े 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह टर्मिनल बनने के बाद हवाई गतिविधियां शुरू होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि रनवे और बाकी व्यवस्था पहले से बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि अभी तक अंबाला का एयरफोर्स का ये स्टेशन सिविल एअरपोर्ट नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराजा अग्रसेन की जयंती की

बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिसार में भी महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है। लगातार 3 साल से काम चल रहा है और जल्द ही इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की प्रारंभ में उसे हवाई अड्डे से कोई न कोई गतिविधि अवश्य शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हवाई दृष्टि से यद्यपि प्रारंभ में एक भी एयरपोर्ट ऐसा नहीं था जो हरियाणा की धरती पर हो। परंतु हम धीरे–धीरे

# साप्ताहिक सूचना पत्र

एविएशन सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम का विकास दिल्ली हवाई अड्डे की नजदीकी के कारण ही संभव हुआ है।

उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चाहे रेल हो, रोड हो, हवाई यात्रा हो, जब तक इसका निर्माण होगा तो विकास के फल बहुत नीचे तक पहुँचेंगे। इसी दिशा में रेल नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है। करनाल से यमुनानगर की रेल लाइन की भी मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने हरियाणा में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को भी मंजूर किया है। लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए मंजूर किए हैं। इनमें से कई राजमार्ग बन गए हैं और कई निर्माणाधीन हैं।

उन्होंने कहा कि 152 डी राजमार्ग अंबाला को कोटपूतली से जोड़ता है। पहले जो यात्रा के लिए 10 घंटे लगते थे, वह आज 5 से 6 घंटे में पूरी होती है। इतना ही नहीं, अंबाला के पश्चिमी बाईपास का भी लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। इसी तर्ज पर अंबाला के पूर्वी बाईपास को भी मंजूर किया गया है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा का नागरिक देश के अन्य प्रांतों की तुलना में अच्छा रोजगार प्राप्त कर रहा है। अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा पूरे देश में सबसे आगे है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 95 हजार रुपये है।